दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 12.11.2013
उद्घोषित तिथि: 10.12.2013

<u>नि.अ.प्र.(मूल पक्ष) 139/2013, सि .सं .वि.17920/2013 (रोक के लिए)</u>

स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री दिनेश अगनानी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री लीना टुटेजा, अधिवक्ता।

बनाम

मैसर्स मिलेनियम वायर्स (प्राइवेट) लिमिटेड व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: प्रत्यर्थी सं. 5 के लिए श्री अजय मोंगा सह श्री अतीव के. माथुर और श्री देवमणि बंसल, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट
माननीय न्यायमूर्ति श्री नजमी वजीरी

<u>न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट</u>

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल वाद (मूल पक्ष) 545/2012 में सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "*सि.प्र.स.*") के आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध है। इस वाद में - मिलेनियम वायर्स (इसके बाद "मिलेनियम") प्रथम वादी और

स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी, द्वितीय वादी) ने इलाहाबाद बैंक के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की; इसने चौथे प्रतिवादी, मलायन बैंक (इसके बाद "विदेशी बैंक") सहित अन्य प्रतिवादीगण को एसटीसी के आदेश पर इलाहाबाद बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट पत्र (एल.सी.) को स्वीकार करने से रोकने की भी मांग की।

2. यह वाद एसटीसी और मिलेनियम के बीच अविरल विक्षेप तांबे की छड़ों के आयात हेतु एक "उपसदस्यता" समझौते (दिनांक 02.12.2011, इसके बाद *"ए.ए."*) से संबंधित है। मिलेनियम, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपने मामले के अनुसार, सिंगापुर और मलेशिया में स्थित समूह कंपनियों सिनर्जिक मटेरियल सर्विसेज पीटीई लिमिटेड और सिनर्जिक इंडस्ट्रियल मटेरियल सर्विसेज मलेशिया से ऐसी छड़ें आयात कर रहा था (इसके बाद क्रमशः *"सिनर्जिक, सिंगापुर"* और *"सिनर्जिक, मलेशिया"* और सामूहिक रूप से *"सिनर्जिक कंपनियां"*)। 400 मीट्रिक टन छड़ें आयात करने के उद्देश्य से, एसटीसी और मिलेनियम ने समझौता किया। ए.ए. के तहत, एसटीसी को सिनर्जिक कंपनियों के माध्यम से मिलेनियम के लिए छड़ें आयात करनी थीं। इसके अतिरिक्त, समझौते में यह भी निर्धारित किया गया है कि मिलेनियम एसटीसी को एसटीसी द्वारा खोले जाने वाले क्रेडिट पत्र के मूल्य के 25% के अग्रिम के रूप में मार्जिन मनी प्रदान करेगा (करार का खंड 4), साथ ही 25% नकद अग्रिम और एसटीसी के पक्ष में माल के मूल्य के

102.5% के लिए एक उत्तर-दिनांकित चेक के साथ-साथ एक कानूनी वचनबद्धता भी प्रदान करेगा। (करार का खंड 3)। ए.ए. एसटीसी के व्यापार मार्जिन (ए.ए. का खंड 5) के लिए भी प्रावधान करता है, और खंड 7 में महत्वपूर्ण रूप से यह निर्धारित करता है कि मिलेनियम,

> *"7.....आपूर्तिकर्ता/निर्माता द्वारा ऋण पत्तन पर जारी मात्रा और गुणवत्ता प्रमाणपत्र की स्वीकृति को मंजूरी देते हैं। इसलिए, क्रेता [एमडब्ल्यूपीएल] यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता और मात्रा क्रम में है....."*

3. लेन-देन की संरचना के तहत, एसटीसी द्वारा इलाहाबाद बैंक के माध्यम से एक एल.सी. खोला जाना था, जो विदेशी बैंक (बातचीत करने वाले और लाभार्थी बैंक) के माध्यम से दो सिनर्जिक कंपनियों को देय था। एसटीसी और मिलेनियम ने वादपत्र में कहा कि लेन-देन जिस तरह से किया गया वह इस प्रकार था: मिलेनियम द्वारा दो सिनर्जिक कंपनियों को मौखिक आदेश दिए गए और उसके बाद, बाद में एसटीसी को बिक्री संविदा/प्रोफार्मा चालान भेजे गए। इसके बाद प्रोफार्मा चालान सिनर्जिक, सिंगापुर द्वारा एसटीसी के पक्ष में जारी किए जाने थे, जिसमें विशेष रूप से मिलेनियम का नाम "ए/सी - मिलेनियम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में उल्लेख किया गया था। उक्त प्रोफार्मा चालान की स्वीकृति पर, दोनों सिनर्जिक कंपनियों द्वारा अंतिम चालान जारी किया जाना था, जिसे मिलेनियम द्वारा स्वीकृति मिलने पर दोनों कंपनियों को वापस भेजा जाना था, और यह एक तरफ एसटीसी/मिलेनियम और दूसरी तरफ दोनों सिनर्जिक कंपनियों के बीच संविदा का गठन करता है। उस स्तर पर, एसटीसी

द्वारा इलाहाबाद बैंक के माध्यम से एल.सी. खोले जाने थे, जो विदेशी बैंक के माध्यम से दोनों सिनर्जिक कंपनियों को देय थे।

4. इस व्यवस्था के अनुसार, छड़ें मलेशिया के पोर्ट क्लैंग से भेजी गईं, जिनका अंतिम गंतव्य लुधियाना का अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो था। सिनर्जिक कंपनियों द्वारा सामान्य तौर पर कई दस्तावेज इलाहाबाद बैंक, जारीकर्ता बैंक को भेजे गए, जिनकी एक प्रति एसटीसी को भी भेजी गई। इनमें वहन पत्र, क्रेडिट पत्र, लाभार्थी प्रमाणपत्र, लाभार्थी का वचन पत्र, अनुलिपि पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट, परीक्षण प्रमाणपत्र, प्राप्त आयात बिलों की सूचना, चालान, पैकिंग सूची, समुद्री कार्गो बीमा पॉलिसी, मलेशियाई मूल का प्रमाणपत्र और शिपिंग एजेंट का प्रमाणपत्र शामिल थे। यहां यह कहा गया है कि इन दस्तावेजों की अग्रिम प्रति कूरियर के माध्यम से एसटीसी को भेजी गई थी, जिसने बदले में मिलेनियम से स्वीकृति मांगी थी। एसटीसी ने दावा किया कि उपरोक्त दस्तावेजों के प्रेषण की कूरियर रसीद, मलायन बैंक को एल.सी. के तहत प्रस्तुत किए गए परक्राम्य दस्तावेजों में से एक थी और इलाहाबाद बैंक को भेजी गई थी। एसटीसी ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत, सिनर्जिक कंपनियां भुगतान जारी करने के लिए विदेशी बैंक के साथ एल.सी. पर बातचीत कर सकती हैं, जिसके बदले में इलाहाबाद बैंक से राशि का दावा करने की हकदार थीं।

5. एसटीसी द्वारा सिनर्जिक, सिंगापुर से छड़ों के आयात के लिए कुल चार एल.सी. खोले गए। ये थे:

क. एल/सी सं. 0189111एफएलयू000150, दिनांक 07.12.2011 को खोला गया। इस पर मलायन बैंक द्वारा इलाहाबाद बैंक के साथ 14.12.2011 को बातचीत की गई। मिलेनियम द्वारा मलायन बैंक को 23.12.2011 को स्वीकृति दी गई। माल की शिपमेंट के लिए वहन पत्र की तारीख 08.12.2011 थी। इस एल.सी. के लिए अंतिम भुगतान मलायन बैंक द्वारा सिनर्जिक, सिंगापुर को किया गया है।

ख. एल/सी सं. 0189111एफएलयू000151, दिनांक 07.12.2011 को खोली गई। इस पर मलायन बैंक द्वारा इलाहाबाद बैंक के साथ 12.12.2011 को बातचीत की गई। मिलेनियम द्वारा विदेशी बैंक को 31.12.2011 को स्वीकृति दी गई। माल की शिपमेंट के लिए वहन पत्र की तारीख 09.12.2011 थी। इस एल.सी. के लिए अंतिम भुगतान विदेशी बैंक द्वारा सिनर्जिक, सिंगापुर को किया गया है।

ग. एल/सी सं. 0189111एफएलयू000154, दिनांक 17.12.2011 को खोली गई। इस पर विदेशी बैंक द्वारा इलाहाबाद बैंक के साथ 22.12.2011 को बातचीत की गई। माल की शिपमेंट के लिए वहन पत्र की तारीख 31.12.2011 थी। इस एल.सी. के लिए अंतिम भुगतान विदेशी बैंक द्वारा सिंगापुर के सिनर्जिक को किया गया है।

घ. एल.सी. सं. 0189111एफएलयू000159, दिनांक 02.01.2012 को खोला गया। विदेशी बैंक द्वारा 06.01.2012 को इलाहाबाद बैंक के साथ इस पर बातचीत की गई। मिलेनियम द्वारा 16.01.2012 को विदेशी बैंक को स्वीकृति प्रदान की गई। माल की शिपमेंट के लिए वहन पत्र की तारीख 07.01.2012 थी।

6. वादी, मिलेनियम और एसटीसी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया कि दोनों सिनर्जिक कंपनियों ने एसटीसी के साथ धोखाधड़ी की है, क्योंकि उत्पादों के शिपमेंट से संबंधित दस्तावेज झूठे और मनगढ़ंत थे। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष और वर्तमान में अपील ज्ञापन में, एसटीसी द्वारा कथित धोखाधड़ी के उदाहरणों पर जोर दिया गया है। यह तर्क दिया गया कि सिनर्जिक कंपनियों ने एसटीसी को प्रासंगिक दस्तावेजों (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) के साथ कूरियर भेजने के बारे में गलत बयान दिए, और डीएचएल और स्काईनेट कूरियर (संबंधित कूरियर कंपनियों) के साथ जांच करने पर, शिपमेंट वेबिल नंबरों में एसटीसी को भेजे गए किसी भी पैकेज से जुड़ा हुआ नहीं पाया गया, या ये वेबिल नंबर मौजूद नहीं थे। इसके आधार पर, यह तर्क दिया गया कि दोनों सिनर्जिक कंपनियों ने संबंधित दस्तावेजों को गढ़ा था, और इस प्रकार, एसटीसी के साथ धोखाधड़ी की।

7. इसके अतिरिक्त, वादपत्र के आरोपों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि शिपमेंट के लिए वहन पत्र भी जाली थे, क्योंकि शिपिंग एजेंट ने उन्हें कभी जारी करने से इनकार किया था, और वास्तव में कोई शिपमेंट भौतिक रूप से नहीं भेजा गया था, जैसा कि एसटीसी और मिलेनियम को गलत तरीके से बताया गया था। साथ ही, पोर्ट क्लैंग के अधिकारियों के साथ पत्राचार के आधार पर, यह तर्क दिया गया कि जिन जहाजों पर शिपमेंट भेजे जाने का आरोप लगाया गया था, वे वहन पत्र द्वारा बताए गए दिनों पर बंदरगाह पर लोडिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे, जो धोखाधड़ी की ओर इशारा करता है। इसलिए, यह देखते हुए कि वहन पत्र, जो निर्यात का अंतिम प्रमाण थे, गढ़े गए थे, यह तर्क दिया गया कि धोखाधड़ी के स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध हैं, ताकि इस मामले में क्रेडिट पत्रों को रद्द किया जा सके।

8. इन तर्कों तथा एसटीसी और मिलेनियम सहित दोनों सिनर्जिक कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, वादीगण, एसटीसी और मिलेनियम ने सिनर्जिक, सिंगापुर के विरुद्ध विवादित एल.सी. के अंतर्गत किसी भी लाभ का दावा करने से स्थायी, अनिवार्य तथा सतत निषेधाज्ञा तथा विदेशी बैंक के विरुद्ध हेतु विद्वान एकल न्यायाधीश से संपर्क किया।

9. प्रतिवादीगण, अर्थात सिनर्जिक कंपनियां और विदेशी बैंक, समन के जवाब में, पेश हुए और वाद के दावे का विरोध किया। विदेशी बैंक ने सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र को खारिज करने के लिए एक

आवेदन भी दायर किया। इसमें, यह आग्रह किया गया कि उसने दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया था क्योंकि वे एल.सी. की शर्तों के अनुरूप थे। एल.सी. पर क्रमशः 12, 14 और 22 दिसंबर 2011 और 6 जनवरी 2012 को बातचीत की गई थी। तदनुसार राशि सिनर्जिक सिंगापुर को भुगतान की गई थी। यह रुख है कि एसटीसी और सिनर्जिक सिंगापुर के बीच कोई भी विवाद यूसीपी-600 (डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, छठा संस्करण) के अनुसार विदेशी बैंक को की जाने वाली प्रतिपूर्ति को बाधित नहीं कर सकता है, जिसे इसके बाद इसके संक्षिप्त नाम "यूसीपी-600" से संदर्भित किया जाता है। यह कहा गया है कि विदेशी बैंक को इलाहाबाद बैंक से यूसीपी-600 के अनुच्छेद 16 के अनुसार कोई नोटिस नहीं मिला। यह कहा गया कि एल.सी. सं. 151 के संबंध में, उक्त इलाहाबाद बैंक से यूसीपी-600 के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। इलाहाबाद बैंक से 31 जनवरी 2012 को एक संदेश प्राप्त हुआ कि वह उक्त एल.सी. के अंतर्गत भुगतान नहीं करेगा क्योंकि एसटीसी ने "आरोप लगाया है कि दस्तावेज फर्जी हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट पर धोखाधड़ी से बातचीत की गई है।" एल.सी. सं. 154 के संबंध में, रुख यह है कि विदेशी बैंक को यूसीपी-600 के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत एसटीसी से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। इसे वादी के अधिवक्तागण से 2 मार्च 2012 के आदेश की प्रति 15 मार्च 2012 को ही प्राप्त हुई। एल.सी. सं. 159 के संबंध में यह कहा गया है कि इलाहाबाद बैंक ने 16 जनवरी 2012 को एक संदेश के माध्यम से दस्तावेजों की

प्राप्ति की पुष्टि की और भुगतान करने का वचन दिया। हालांकि, बाद में इसने दोहराया कि एस.टी.सी. ने आरोप लगाया था कि दस्तावेज फर्जी थे।

10. इसके विपरीत, एसटीसी ने तर्क दिया था कि एल.सी. 150, 154 और 159 के संबंध में, *"वादी (अर्थात एसटीसी और एमडब्ल्यूपीएल) को पता चला कि प्रतिवादी सं. 2 कंपनी ने निर्यात को प्रदर्शित करने के लिए कूरियर रसीद का निर्माण किया था और गलत तरीके से घोषित किया था कि फैक्स संदेश भेजा गया है और निर्यात को साबित करने के लिए अन्य दस्तावेजों को भी गढ़ा है"*। एल.सी. 151 के संबंध में, एसटीसी ने तर्क दिया था कि प्राप्त दस्तावेजों को विधिवत खारिज कर दिया गया था और यह तथ्य इलाहाबाद बैंक को सूचित किया गया था।

11. इस संदर्भ में, इलाहाबाद बैंक का रुख यह था कि "वादी सं. 2 से प्रतिवादी सं. 4 से प्राप्त दस्तावेजों के सेट की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, उत्तर देने वाले प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 4 को निम्नलिखित तीन एल.सी. के संबंध में भुगतान की देय तिथियों की सलाह देते हुए इसे सूचित किया: (क) 0189111एफएलयू000150 (ख) 0189111एफएलएस000154 (ग) 0189112एफएलयू000159।" इस प्रकार, इलाहाबाद बैंक पुष्टि करता है कि इन 3 एल.सी. के संबंध में, कम से कम, अनुपालन प्रस्तुति की गई थी, और एसटीसी (और मिलेनियम) से स्वीकृति की गई थी।

12. विदेशी बैंक ने तर्क दिया कि यूसीपी-600 के अनुसार, एक बार जब बातचीत करने वाले बैंक द्वारा एल.सी. का भुगतान कर दिया जाता है, तो भुगतान करना जारीकर्ता बैंक का अपरिवर्तनीय वचन है, खासकर जब उसने दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया है और परिपक्वता तिथि पर भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। यह कहा गया है कि इलाहाबाद बैंक, सिनर्जिक कंपनियों और विदेशी बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है, इसलिए वादपत्र को खारिज किया जाना चाहिए। विदेशी बैंक ने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम बैंक ऑफ इंडिया, (1981) 2 एससीसी 766 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया। इसने कहा कि उसके (विदेशी बैंक) द्वारा इलाहाबाद बैंक को धोखाधड़ी के किसी भी जानकारी के बिना भुगतान किया गया था और इसलिए, इलाहाबाद बैंक यूसीपी-600 के अनुसार प्रत्येक एल.सी. के तहत अपनी प्रतिबद्धता का स्वीकार करने के लिए बाध्य था। एल.सी. 150, 154 और 159 के संबंध में, विदेशी बैंक, इलाहाबाद बैंक के रुख के अनुरूप, यह मानता है कि दस्तावेजों को एसटीसी द्वारा स्वीकार किया गया था, और इस प्रकार, उस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है। एल.सी. 151 के संबंध में, विदेशी बैंक का तर्क है कि, फिर से, यूसीपी-600 के अनुच्छेद 16 के तहत नोटिस दिया गया था, ताकि एल.सी. के तहत भुगतान को यूसीपी-600 के ढांचे के भीतर रोका जा सके, जिसके बारे में तर्क दिया जाता है कि यह एसटीसी/मिलेनियम

और सिनर्जिक कंपनियों के बीच संविदात्मक संबंधों के विपरीत, पूरे एल.सी. लेनदेन को विनियमित करता है।

13. विदेशी बैंक ने 2 मार्च 2012 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम रोक को भी हटाने की मांग की। यह तर्क देने के लिए यूसीपी-600 के अनुच्छेद 4, 5, 15 और 16 पर भरोसा किया गया था कि अंतर्निहित संविदा क्रेडिट पत्र से स्वतंत्र है, जो यूसीपी-600 के संदर्भ में प्रस्तुति का अनुपालन करने पर भुगतान करने के लिए एक अलग समझौते का गठन करता है। विशेष रूप से, यह तर्क दिया गया कि एक बार जब एल.सी. के तहत भुगतान जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, और एल.सी. की शर्तों के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं, तो बैंक खरीदार के विचारों के बावजूद भुगतान करने के लिए बाध्य है, क्योंकि विक्रेता के खिलाफ बाद में होने वाले किसी भी विवाद को वैकल्पिक कार्यवाही में उठाया जाना है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि "*चूंकि दस्तावेजों में कोई विसंगति नहीं है ... ऐसी परिस्थितियों में वादी सं. 2 द्वारा दस्तावेजों को अस्वीकार करना कोई परिणाम नहीं है।*"

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश VII, नियम 11 के तहत वाद खारिज कर दिया, क्योंकि वाद हेतुक बताने में विफलता थी। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दो सिनर्जिक कंपनियों के खिलाफ एसटीसी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के विभिन्न आरोपों को दर्ज किया और उनकी सराहना की, लेकिन दो

आधारों पर वादपत्र खारिज कर दी गई: पहला, कि ऋण पत्र एक स्वतंत्र लेनदेन का गठन करता है, जिसके तहत दायित्व अंतर्निहित संविदा की पेचीदगियों पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि विवादित बैंक को आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर निर्भर होते हैं; दूसरा, कि क्रेडिट पत्रों में हस्तक्षेप करने पर सामान्य निषेध को देखते हुए, एकमात्र सीमित अपवाद विक्रेता द्वारा क्रेता पर की गई धोखाधड़ी है, यदि, महत्वपूर्ण रूप से, भुगतान करने वाले बैंक को ऐसी धोखाधड़ी की सूचना है। ऐसी सूचना के अभाव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा, एल.सी. के तहत भुगतान करने का दायित्व जारी रहता है और धोखाधड़ी करने वाले पक्षकार को पैसे की वसूली के लिए विक्रेता के खिलाफ स्वतंत्र वाद चलाना होगा। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीएस(ओएस) 545/2012 में अंतर्वर्ती आवेदन सं. 4103/2012 में दिनांक 02.03.2012 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम रोक को भी रद्द कर दिया। इस निर्णय पर पहुँचने में, तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले में शामिल विधि के बिन्दुओं पर इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

> *"30. अतः, एल.सी. के संबंध में विधि को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:*
>
> *(i) न्यायालय को बैंक गारंटी या एल.सी. की वसूली पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा आदेश देने में धीमा होना चाहिए;*
> *(ii) उपरोक्त नियम के दो अपवाद हैं। पहला यह है कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि गंभीर प्रकृति का धोखा किया गया है तथा बैंक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा यह है कि ऐसा अन्याय होना चाहिए जिससे गारंटर के लिए स्वयं की*

प्रतिपूर्ति करना असंभव हो जाए, या जिसके परिणामस्वरूप संबंधित पक्षकारगण में से किसी एक को अपूरणीय क्षति या अन्याय हो।

(iii) केवल धोखाधड़ी का आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी के तथ्य के साथ-साथ बैंक को ऐसी धोखाधड़ी के बारे में जानकारी होने के स्पष्ट साक्ष्य होने चाहिए।"

15. धोखाधड़ी के बारे में विदेशी बैंक की जानकारी पर किसी भी ठोस दलील के अभाव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि वादपत्र में प्रकटीकरण की गई वाद हेतुक जिसमें केवल दो सिनर्जिक कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप शामिल थे और विदेशी बैंक द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी भी विवरण या धोखाधड़ी के बारे में विदेशी बैंक को दी गई सूचना नहीं थी, अंतिम प्रार्थना के योग्य होने के लिए अपर्याप्त था, और इस प्रकार सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत अस्वीकार किए जाने योग्य था।

16. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि यहाँ जिस धोखाधड़ी का उल्लेख किया गया है, वह ऐसी है जिसे स्पष्ट रूप से "घोर" कहा जा सकता है और जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है, ताकि इक्विटी में उपाय को उचित ठहराया जा सके। यह तर्क दिया गया कि दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वहन पत्र संविदा के अनुसार माल भेजे जाने की तिथि से बहुत पहले जारी किए गए थे और विशेष रूप से क्रेडिट पत्रों की शर्तों के विपरीत थे। एसटीसी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि निर्देश स्पष्ट रूप से दिसंबर के अंत तक माल भेजने के थे; फिर भी वहन पत्र से पता चला कि इसे कम से कम दो सप्ताह पहले जारी

किया गया था; इसके अतिरिक्त, स्पष्ट रूप से एक हेरफेर था, जो नग्न आंखों से दिखाई देता है। इलाहाबाद बैंक द्वारा विदेशी बैंक को असंगत दस्तावेजों के बारे में सूचित करने और उन्हें यूसीपी-600 के अनुसार वापस करने में विफलता या चूक का मतलब यह नहीं था कि न्यायालय को न्यायसंगत राहत, निषेधाज्ञा देने के क्षेत्राधिकार से वंचित होना पड़ा।

17. इस मामले में जो सीमित प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या ऋण पत्र के तहत बातचीत करने वाले बैंक द्वारा भुगतान पर रोक लगाई जा सकती है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम बैंक ऑफ इंडिया, एआईआर 1981 एससी 1426 में माना है,

> *"48.....[ ] केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही न्यायालय बैंकों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अपरिवर्तनीय दायित्वों की मशीनरी में हस्तक्षेप करेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की जीवन-शक्ति हैं। ऐसे दायित्वों को बैंकिंग श्रृंखला के दोनों छोर पर व्यापारियों के बीच अंतर्निहित अधिकारों और दायित्वों के लिए संपार्श्विक माना जाता है। धोखाधड़ी के स्पष्ट मामलों को छोड़कर, जिसके बारे में बैंकों को जानकारी है, न्यायालय व्यापारियों को संविदाओं के तहत अपने विवादों को मुकदमेबाजी या मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए छोड़ देंगे, जैसा कि उनके लिए उपलब्ध है या संविदाओं में निर्धारित है। न्यायालय ऐसे दावों को लागू करने में उनकी कठिनाइयों से चिंतित नहीं हैं; ये जोखिम हैं जो ये व्यापारी उठाते हैं। इस मामले में वादी ने गारंटी के बिना शर्त शब्दों का जोखिम उठाया। बैंकों की मशीनरी और प्रतिबद्धताएँ एक अलग स्तर पर हैं। उन्हें न्यायालयों के हस्तक्षेप से मुक्त, स्वीकार होने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्यथा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में विश्वास को अपूरणीय क्षति हो सकती है।"*

यह सिद्धांत अनुच्छेद 4(क), यूसीपी-600 में भी परिलक्षित होता है, जो एल.सी. संविदाओं के संबंध में बाध्यकारी है:

> *"(क) ऋण अपनी प्रकृति से बिक्री या अन्य संविदा से अलग लेनदेन है जिस पर यह आधारित हो सकता है। बैंक किसी भी तरह से ऐसे संविदा से संबंधित या बाध्य नहीं हैं, भले ही ऋण में इसका कोई भी संदर्भ शामिल हो। परिणामस्वरूप, ऋण के तहत किसी अन्य दायित्व को स्वीकार करने, बातचीत करने या उसे पूरा करने के लिए बैंक का उपक्रम आवेदक द्वारा जारीकर्ता बैंक या लाभार्थी के साथ अपने संबंधों के परिणामस्वरूप दावों या बचाव के अधीन नहीं है।*
>
> *किसी भी मामले में लाभार्थी बैंकों या आवेदक और जारीकर्ता बैंक के बीच मौजूद संविदात्मक संबंधों का लाभ नहीं उठा सकता है।"*

इसी तरह, अनुच्छेद 5 भी भुगतान जारी करने के लिए बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और उन उत्पादों/माल के बीच अंतर बनाता है जिनसे वे दस्तावेज अंततः संबंधित हैं, निम्नलिखित शब्दों में:

> *"बैंक दस्तावेजों से निपटते हैं, न कि उन वस्तुओं, सेवाओं या प्रदर्शन से जिनसे दस्तावेज संबंधित हो सकते हैं।"*

18. भारतीय कानून में यह सुस्थापित है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से नोट किया है, कि एल.सी. के तहत भुगतान पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब (क) अपूरणीय क्षति की संभावना हो, जिसमें खरीदार बातचीत करने वाले बैंक द्वारा पहले ही जारी किए गए पैसे को वापस पाने में सक्षम नहीं हो सकता है, या (ख) जहां अंतर्निहित लेनदेन में धोखाधड़ी है जिसे बैंक के ध्यान में लाया गया है। फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम वीएम जोग इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य, (2001) 1 एससीसी 663 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी थी:

> "57. *इस न्यायालय के कई निर्णयों में यह माना गया है कि न्यायालयों को बैंक गारंटी या साख पत्रों के नकदीकरण पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा नहीं देनी चाहिए। दो अपवादों का उल्लेख किया गया है - (i) धोखाधड़ी और (ii) अपूरणीय क्षति। यदि वादी प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सक्षम है कि मामला इन दो अपवादों के अंतर्गत आता है, तो सि.प्र.स. के आदेश 39, नियम 1 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। यह भी माना गया है कि बैंक गारंटी या साख पत्र का संविदा विक्रेता और खरीदार के बीच मुख्य संविदा से स्वतंत्र है। यह अनुच्छेद 3 और यूसीपी (1983 संशोधन) से भी स्पष्ट है। अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी या साख पत्र के मामले में क्रेता इस आधार पर बैंकर के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता कि विक्रेता द्वारा संविदा का उल्लंघन किया गया है।*

19. विदेशी बैंक के इस मामले में बैंक का दायित्व एल.सी. को स्वीकार करना है, और न्यायालय के शब्दों में,

> "यदि विक्रेता प्रथम दृष्टया बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्तों का अनुपालन करता है, अर्थात, यदि विक्रेता बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है। यदि बैंक दस्तावेजों को देखकर संतुष्ट हो जाता है कि वे बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट में उल्लिखित दस्तावेजों की सूची के अनुरूप हैं और उनमें कोई विसंगति नहीं है, तो वह विक्रेता की नकदीकरण की मांग को मानने के लिए बाध्य है।"

20. यह दायित्व केवल इसलिए प्रभावित नहीं होता है क्योंकि क्रेता संविदा के उचित निष्पादन पर विवाद करता है। जब तक प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ एल.सी. की शर्तों के अनुसार हैं, तब तक दायित्व अप्रभावित है। यही एल.सी. की दस्तावेजी स्वायत्तता का सार है। इस मामले में, एल.सी. 150, 154 और 156 के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ सही थे, और एसटीसी या मिलेनियम

द्वारा इस पर कभी विवाद नहीं किया गया। इसके विपरीत, एसटीसी ने इन तीन एल.सी. के संबंध में इलाहाबाद बैंक को अपनी स्वीकृति से अवगत कराने की बात स्वीकार की। एल.सी. 151 के संबंध में, विदेशी बैंक की स्थिति यह है कि दस्तावेज़ एल.सी. के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, और इसलिए, भुगतान करने का दायित्व शुरू हो गया। यहाँ, अनुच्छेद 16, यूसीपी-600 महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:

"विसंगत दस्तावेज, छूट और नोटिस:

(क) जब कोई नामित बैंक अपने नामांकन पर कार्य करता है, कोई पुष्टि करने वाला बैंक, यदि कोई हो, या जारीकर्ता बैंक यह निर्धारित करता है कि कोई प्रस्तुति अनुपालन नहीं करती है, तो वह स्वीकार या बातचीत करने से इनकार कर सकता है।

(ख) जब कोई जारीकर्ता बैंक यह निर्धारित करता है कि कोई प्रस्तुति अनुपालन नहीं करती है, तो वह अपने एकमात्र निर्णय में विसंगतियों की छूट के लिए आवेदक से संपर्क कर सकता है। हालांकि, यह उप-अनुच्छेद 14 (ख) में उल्लिखित अवधि को आगे नहीं बढ़ाता है।
(ग) जब कोई नामित बैंक अपने नामांकन पर कार्य करता है, कोई पुष्टि करने वाला बैंक, यदि कोई हो, या जारीकर्ता बैंक स्वीकार या बातचीत करने से इनकार करने का निर्णय करता है, तो उसे प्रस्तुतकर्ता को इस आशय का एक नोटिस देना होगा।

नोटिस में यह अवश्य बताया जाना चाहिए:
(1) कि बैंक स्वीकार या बातचीत करने से इनकार कर रहा है; और
(2) प्रत्येक विसंगति जिसके संबंध में बैंक स्वीकार या बातचीत करने से इनकार करता है; और
(3) (क) कि बैंक प्रस्तुतकर्ता से आगे के निर्देश मिलने तक दस्तावेजों को अपने पास रखे हुए है; या

(ख) कि जारीकर्ता बैंक दस्तावेजों को तब तक अपने पास रखे हुए है जब तक कि उसे आवेदक से छूट प्राप्त न हो जाए और वह उसे स्वीकार करने के लिए सहमत न हो जाए, या छूट स्वीकार करने के लिए सहमत होने से पहले प्रस्तुतकर्ता से आगे के निर्देश प्राप्त न हो जाएं; या
(ग) कि बैंक दस्तावेजों को वापस कर रहा है; या
(घ) कि बैंक प्रस्तुतकर्ता से पहले प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है।
(घ) उप-अनुच्छेद 16 (ग) में अपेक्षित सूचना दूरसंचार द्वारा या, यदि यह संभव न हो, तो अन्य त्वरित साधनों द्वारा प्रस्तुति के दिन के बाद पांचवें बैंकिंग दिवस की समाप्ति से पहले दी जानी चाहिए।
(ड) अपने नामांकन पर कार्य करने वाला नामित बैंक, पुष्टि करने वाला बैंक, यदि कोई हो, या जारीकर्ता बैंक, उप-अनुच्छेद 16 (ग) (iii) (क) या (ख) द्वारा अपेक्षित सूचना प्रदान करने के बाद, किसी भी समय प्रस्तुतकर्ता को दस्तावेज वापस कर सकता है।

(च) यदि कोई जारीकर्ता बैंक या पुष्टि करने वाला बैंक इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो उसे यह दावा करने से रोक दिया जाएगा कि दस्तावेज अनुपालन प्रस्तुति नहीं करते हैं।

(छ) जब कोई जारीकर्ता बैंक स्वीकार करने से इनकार करता है या कोई पुष्टि करने वाला बैंक स्वीकार करने या बातचीत करने से इनकार करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार उस आशय की सूचना दे चुका है, तो वह तब की गई किसी भी प्रतिपूर्ति पर ब्याज सहित वापसी का दावा करने का हकदार होगा।

21. इसलिए, अनुच्छेद 16(च) जारीकर्ता और पुष्टि करने वाले बैंकों पर अनुच्छेद 16 के प्रावधानों का पालन करने में तत्परता बरतने की जिम्मेदारी डालता है, जिसके विफल होने पर दस्तावेजों को खरीदार से छूट के साथ या उसके बिना, एल.सी. के तहत भुगतान जारी करने के उद्देश्य से अनुपालन

प्रदर्शन का गठन करने वाला माना जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से, यह निर्णय कि क्या दस्तावेज अनुपालन प्रस्तुति का गठन करते हैं, पूरी तरह से जारीकर्ता बैंक (अर्थात् इसका "एकमात्र निर्णय", उप-खंड (ख) के संदर्भ में, इस मामले में, इलाहाबाद बैंक) का है, जो दस्तावेजों में विसंगति पाए जाने पर, छूट के लिए खरीदार से संपर्क कर सकता है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां जारीकर्ता बैंक यह निर्णय लेता है कि दस्तावेज खंड (ग) के संदर्भ में एल.सी. के तहत अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, ऐसी सूचना "प्रस्तुति के दिन के बाद पांचवें बैंकिंग दिन के समापन से पहले नहीं दी जानी चाहिए।"

22. इस प्रकार, यदि एल.सी. के तहत भुगतान पर रोक लगाई जानी है, तो उस अनुच्छेद की शर्तों के अंतर्गत धारा 16 के तहत नोटिस देना अनिवार्य है। इस मामले में, एल.सी. 150, 154 और 159 के संबंध में, दस्तावेजों को इलाहाबाद बैंक द्वारा स्वीकार किया गया था, और धारा 16 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इस प्रकार विदेशी बैंक द्वारा उन एल.सी. के तहत भुगतान किया गया। एल.सी. 151 के संबंध में, एकमात्र एल.सी. जिसके बारे में एस.टी.सी./मिलेनियम ने दावा किया है कि उसने दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया है, दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं: *पहला,* यू.सी.पी. के अनुच्छेद 16 के तहत, यह इलाहाबाद बैंक का एकमात्र निर्णय है कि वह यह निर्धारित करे कि दस्तावेज अनुपालन प्रस्तुति का गठन करते हैं या नहीं, और यदि वह बैंक ऐसा निर्धारित करता है, तो खरीदार (एस.टी.सी./मिलेनियम) द्वारा अस्वीकृति निर्णायक नहीं

है। हालांकि, यदि इलाहाबाद बैंक यह निर्धारित करता है कि दस्तावेज अनुपालन प्रस्तुतिकरण का गठन नहीं करते हैं, तो एसटीसी/मिलेनियम द्वारा इसे माफ किया जा सकता है। हालांकि, इस मामले में, एल.सी. 150, 154 और 159 के संबंध में, ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता; जबकि एल.सी. 151 के संबंध में, इलाहाबाद बैंक द्वारा एल.सी. को स्वीकार करने से इनकार (एसटीसी द्वारा अस्वीकृति की सूचना प्राप्त करने के बाद) विदेशी बैंक द्वारा एल.सी. की प्रस्तुति के 5 दिनों के बाद हुआ। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 16(घ) की शर्तें, 16(च) के साथ पढ़ी गई, स्पष्ट हैं, कि विदेशी बैंक द्वारा बाद में एल.सी. के तहत भुगतान पर आपत्ति नहीं की जा सकती है

23. इस संदर्भ में, यूसीपी-600 और इसके सभी पिछले संस्करणों की स्थिति को याद करना आवश्यक होगा। अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजी ऋण अभ्यास और कानून को ऐसे उपकरणों से निपटने वाले सभी बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के दृष्टिकोण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगी (और कोई यह भी कह सकता है कि सहकारी) प्रयास और भावना के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। ऐसे उपकरणों से निपटने वालों पर मानक बाध्यताओं और बाध्यकारी प्रभाव को पहचानने के महत्व को बार-बार रेखांकित किया गया है। शेट्ज़ और फॉन्टेन, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट लॉ थ्रूआउट द वर्ल्ड (2001) (आईसीसी प्रकाशन सं. 633) में, पैराग्राफ 2.2.4 में राष्ट्रीय कानून और यूसीपी के संबंध पर एक

उपयोगी चर्चा है, जहाँ यूसीपी का अर्थ विवाद में है या यूसीपी में राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मौजूद मुद्दे के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है:

> *"जबकि यूसीपी का उद्देश्य विश्वव्यापी व्यापार प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग समुदाय के हितों की रक्षा करना है, राष्ट्रीय कानून हर देश में अलग-अलग होते हैं। यूसीपी द्वारा स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किए गए मुद्दों पर राष्ट्रीय कानूनों के लागू होने से नियमों का गैर-अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है और उनके उद्देश्य के साथ टकराव हो सकता है। राष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों के आवेदन को सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है। यदि यूसीपी आम तौर पर किसी मुद्दे को संबोधित करता है, लेकिन उसके किसी विशेष पहलू के लिए स्पष्ट समाधान प्रदान नहीं करता है, तो इस बात पर विचार करने का विकल्प भी है कि क्या यूसीपी में निहित सामान्य नियम में कोई समाधान पाया जा सकता है। यूसीपी की व्याख्या उनके उद्देश्यों और मूल्यांकनों के अनुसार आम तौर पर बेहतर होती है।"*

ब्रिटेन में अपील न्यायालय ने ग्लेनकोर इंटरनेशनल एजी बनाम बैंक ऑफ चाइना 1996 (1) लॉयड्स रेप 135 में इस सिद्धांत को मान्यता दी:

> *"अभ्यास आम तौर पर दस्तावेजी क्रेडिट के लिए समान सीमा शुल्क और अभ्यास ("यूसीपी") द्वारा शासित होता है, जो अनुभवी बाजार पेशेवरों द्वारा तय किए गए नियमों का एक कोड है और यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा के तहत रखा जाता है कि कानून अनुभवी बाजार चिकित्सकों की सर्वोत्तम प्रथा और उचित अपेक्षाओं को दर्शाता है। जब यहां और विदेश में न्यायालयों को वर्तमान जैसे प्रश्नों पर निर्णय देने के लिए कहा जाता है, तो वे यूसीपी के अंतर्निहित अंतर्राष्ट्रीय परिणामों को प्रभावी करने का प्रयास करते हैं।"*

24. कुछ हद तक समान परिस्थितियों से निपटते हुए, यूके कोर्ट ऑफ अपील्स ने फोर्टिस बैंक एसए/एनवी व अन्य बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक 2011 (2) लॉयड्स प्रतिनिधि 33 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

> *"यह साख पत्रों के संचालन के लिए मौलिक है कि, जब जारीकर्ता बैंक यह निर्धारित करता है कि दस्तावेज अनुरूप नहीं हैं, तो वह उन्हें अस्वीकार कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो वह दस्तावेजों को अपने पास रखने का हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि अस्वीकृति में यह निहित है कि उसने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उसे या तो उन्हें प्रस्तुतकर्ता के निपटान में या उसके निर्देशों के अनुसार रखना चाहिए या उन्हें वापस करना चाहिए। इसलिए एक बार जब जारीकर्ता बैंक ने दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया है, तो वह अपने चुने हुए विकल्प के अनुसार कार्य करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता है। इस प्रकार, लेख में नोटिस के अनुसार कार्य करने के लिए जारीकर्ता बैंक के दायित्व को स्पष्ट करना आवश्यक नहीं था। यह लेख के शब्दों में निहित था।*
>
> *38 दूसरा, नोटिस के अनुसार कार्य करने का दायित्व वही है जो उपरोक्त पैरा 31-35 में निर्धारित मानक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और व्यापार अभ्यास द्वारा अपेक्षित है। व्यवहार में क्रेडिट पत्रों को काम में लाना आवश्यक है ताकि प्रस्तुतकर्ता उन वस्तुओं से निपट सके जो उन दस्तावेजों द्वारा दर्शाई गई हैं जिन्हें जारीकर्ता बैंक ने अस्वीकार कर दिया है। दस्तावेजों से निपटने में प्रस्तुतकर्ता की अक्षमता के परिणाम इतने प्रसिद्ध हैं कि उन्हें गिनाने की आवश्यकता नहीं है; उदाहरण स्पष्ट हैं जैसे कि खराब होने वाले माल के मामले में, या जहां बाजार गिरता है या जहां जहाज आता है और माल उतारना चाहता है।"*

इस प्रकार, जारीकर्ता बैंक (इस मामले में, इलाहाबाद बैंक) अपनी स्थिति बताने और दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बाध्य था। इसने दस्तावेजों को स्वीकार करने का विकल्प चुना और काफी समय बीत जाने के बाद, विदेशी बैंक को विसंगति के बारे में सूचित किया। स्पष्ट रूप से यूसीपी के अनुच्छेद 16 को ध्यान में रखते हुए यह ऐसा नहीं कर सकता था।

25. धोखाधड़ी के प्रश्न पर आते हुए, एसटीसी ने दोनों सिनर्जिक कंपनियों द्वारा स्वयं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जबकि धोखाधड़ी एल.सी. को स्वीकार करने का अपवाद है, यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी बैंक को भुगतान करने से पहले इस तरह की धोखाधड़ी की सूचना या जानकारी हो, ताकि अपवाद लागू हो सके। इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने यूबीएस एजी बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, 2006 (5) एससीसी 416 में निम्नलिखित शब्दों में विचार किया:

> "31. *इन तीनों अपीलों के तथ्य स्पष्ट और सरल हैं। जारीकर्ता बैंक द्वारा पुष्टिकर्ता बैंक को ऋण पत्र इस अनुरोध के साथ जारी किए गए थे कि लाभार्थी को सूचित किया जाए कि लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों पर बातचीत के आधार पर अपीलार्थी-बैंक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के लिए अपरिवर्तनीय ऋण पत्र स्थापित किया गया है। लाभार्थी द्वारा अपीलार्थी-बैंक को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद, इसने लाभार्थी को ऋण पत्र के तहत भुगतान किया और प्रत्यर्थी-बैंक से इसके लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार था। <u>यदि धोखाधडी का पहले पता लगाया गया होता और अपीलार्थी-बैंक को इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया गया होता और भुगतान करने से पहले उसे सावधान किया गया होता, तो प्रत्यर्थी-बैंक के पास वाद चलाने के लिए एक विचारणीय मुद्दा हो सकता था। इन तीनों मामलों में ऐसा नहीं है। इन मामलों में,</u>*

धोखाधड़ी का पता तब चला जब क्रेडिट पत्रों पर बातचीत हो चुकी थी और इसलिए प्रत्यर्थी-बैंक के घटक द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी को अपीलार्थी-बैंक द्वारा दायर वाद में एक उचित बचाव के रूप में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है।" (जोर दिया गया)।

26. यह तथ्य कि धोखाधड़ी अपने आप में मौजूद थी या है, अपर्याप्त है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी बैंक को इस तरह की धोखाधड़ी की सूचना देना सिद्ध होना चाहिए - एक ऐसा कारक जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाद्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कोल टार रिफाइनिंग कंपनी, (2007) 8 एससीसी 110 में मान्यता दी है, जिसमें कहा गया है कि

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

11.....धोखाधड़ी के तथ्य और बैंक की जानकीरी दोनों के बारे में साक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए....."

27. इसलिए, वाद हेतुक का प्रकटीकरण करने के लिए, दोनों तत्वों का तर्क दिया जाना चाहिए। जबकि इस मामले में वाद में दो सिनर्जिक कंपनियों द्वारा एसटीसी/मिलेनियम पर किए गए कथित धोखाधड़ी के बारे में पर्याप्त दलीलें (और सहायक साक्ष्य) का खुलासा किया गया है, विदेशी बैंक को इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी होने का एकमात्र संदर्भ वाद के पैराग्राफ 17 और 47 में पाया जाता है, जो केवल इस दावे का खुलासा करता है कि विदेशी बैंक सिनर्जिक कंपनियों के साथ "सक्रिय मिलीभगत" में है, और तथ्य "इस संदेह

को जन्म देते हैं कि यह (मलायन बैंक) सिनर्जिक कंपनियों के साथ मिलीभगत रखता है"।

28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि "वाद हेतुक का प्रकटीकरण करने में दलीलों की विफलता पूर्ण विवरण की अनुपस्थिति से अलग है" (लिवरपूल और लंदन एसपी और आई असोन लिमिटेड बनाम एमवी सी सक्सेस आई व अन्य, (2004) 9 एससीसी 512; उसी समय, धोखाधड़ी के मामलों में, न्यायालय ने माना है कि

> "144. .....तथ्यों को बताना आवश्यक है, लेकिन साक्ष्य नहीं, सिवाय कुछ मामलों के जहां दलील किसी गलत बयानी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जानबूझकर, चूक या अनुचित प्रभाव पर निर्भर करती है।"
>
> (जोर दिया गया)

29. वर्तमान मामले में वादपत्र में, बिना किसी विवरण का उल्लेख किए, विदेशी बैंक पर धोखाधड़ी की सूचना के प्रश्न को आकस्मिक और अस्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया है, जो कार्रवाई के कारण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि आईटीसी लिमिटेड बनाम ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य, (1998) 2 एससीसी 70 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, केवल इस परिस्थिति से कि माल नहीं भेजा गया था, स्वतः ही धोखाधड़ी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और आगे के विवरण अभिलेख पर रखे जाने चाहिए। जैसा कि न्यायालय ने नोट किया:

"27..... विक्रेता द्वारा माल की गैर-आवाजाही कई तरह के मान्य या अमान्य कारणों से हो सकती है, विक्रेता संविदा का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में वादी को वादपत्र में 'धोखाधड़ी' शब्द का उपयोग करने और सि.प्र.स. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दायर करके उठाए गए किसी भी आपत्ति को दूर करने की अनुमति नहीं देता है। जैसा कि टी अरिवंदम के मामले में कृष्णा अय्यर, जे ने बताया, वादपत्र में एक शब्द को दोहराने या भ्रम पैदा करने की रस्म को आदेश 7 नियम 11 (क) के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से उजागर किया जा सकता है। चूंकि माल की आवाजाही के बिना धन की निकासी का आरोप 'धोखाधड़ी' के आधार पर वाद हेतुक नहीं बनता है, इसलिए बैंक वादपत्र में इस्तेमाल किए गए 'धोखाधड़ी' या 'गलत बयानी' शब्दों का सहारा नहीं ले सकता है।"

30. इस न्यायालय की राय में, यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, (1988) 1 एससीसी 174 में दिया गया निर्णय भी इस मामले पर पूरी तरह लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि:

"48.....बैंक को, तथापि, यह निर्धारित करने की अनुमति नहीं थी कि विक्रेता ने वास्तव में माल भेजा था या नहीं या माल संविदा की आवश्यकताओं के अनुरूप था या नहीं....." (जोर दिया गया)।

31. वास्तव में, "ऐसी शक्तियों को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक वाद जो निरर्थक है और निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे न्यायालय के समय पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए" (अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, 1986 एससीआर (2) 782, पैराग्राफ 12)। इस प्रकार, ऐसे मामले में, किसी भी विवरण की अनुपस्थिति, या इस दावे का

समर्थन करने के लिए किसी भी साक्ष्य की अनुपस्थिति को देखते हुए कि विदेशी बैंक ने सिनर्जिक कंपनियों के साथ मिलीभगत की, या यहां तक कि इस तरह की धोखाधड़ी की सूचना भी थी, वादपत्र में बताए गए दावे का विफल होना तय है, क्योंकि दलील दी गई वाद हेतुक एसटीसी को उस उपचार का हकदार नहीं बनाता है जिसके लिए वह प्रार्थना करता है। दूसरे शब्दों में, भले ही कथित धोखाधड़ी साबित हो जाती है (एसटीसी/मिलेनियम पर सिनर्जिक कंपनियों द्वारा), इससे यह उपाय नहीं होगा कि विदेशी बैंक को कोई लाभ जारी करने से रोका जाए, या सिनर्जिक कंपनियों को विवादित एल.सी. के तहत कोई लाभ देने से मना किया जाए।

32. इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार अपील और लंबित आवेदन को खारिज किया जाता है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

एस. रवींद्र भट
(न्यायाधीश)

नजमी वजीरी
(न्यायाधीश)

10 दिसंबर, 2013

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*